



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 02, 2017/अग्रहायण 11, 1939

[ग.रा.रा.क्ष.दि. सं. 370

No. 444]

DELHI, SATURDAY, DECEMBER 02, 2017/AGRAHAYANA 11, 1939

[N.C.T.D. No. 370

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

सं. 39/2017-राज्य कर

सं. फा. 03(68)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/781.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "दिल्ली जीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात सीजीएसटी अधिनियम कहा गया है) के अधीन नियुक्त अधिकारी जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) के रूप में प्राधिकृत हैं, दिल्ली जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st December, 2017

No. 39/2017-State Tax

No. F. 3(68)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/781.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “Delhi GST Act”), on the recommendations of the Council, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”) who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as “the said officers”) by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Delhi GST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

आदेश

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

सं. 01/2017 —राज्य कर

राज्य माल एवं सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

सं. फा. 03 (66)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/782.—जहाँ कि राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3), एतर्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है :

अतः अब राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को राज्य माल एवं सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,—
 - (i) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूचि II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिसमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहाँ तक व्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक कि इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।
 - (ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, ऋण या अग्रिम माध्यम से दी जाती हैं जहाँ तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति व्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

यह आदेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

ORDER

Delhi, the 1st December, 2017

No. 01/2017 – State Tax**THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER,**

No. F. 3 (66)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/782.—Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, (Delhi Act 03 of 2017) hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

(i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

(ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

3. This order shall come into force from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of

National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)